भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2748
जिसका उत्तर मंगलवार, 10 मई, 2016 को दिया जाना है।

ऑटोमोबाइल कंपनियों की निगरानी

2748. श्री नाना पटोले:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की ऑटोमोबाइल कंपनियों की निगरानी के लिए आधे दर्जन केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य के विभागों को लगा रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश की ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सरकार से एकल निगरानी एजेंसी गठित करने के लिए अपील की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास ऑटोमोबाइल कंपनियों हेतु एकल विनियामक एजेंसी गठित करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): जी, नहीं।

(घ) और (ङ): सरकार ने राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) की स्थापना के लिए अनुमोदन दे दिया है, जो वाहनों के सभी प्रौद्योगिकी पहलुओं पर विचार करने तथा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए नीति के निर्माण में सहायता के लिए एक केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी।

****